



यह कि वाहन के मालिकों के लिये उनके वाहन के लागू खर्च को जारी रखने का प्रयास हो जायेगा वाहन को न चलाने से कर्तव्य नहीं है। अप्रार्थी को वाहन की आवश्यकता अपनी ओर से कभी एक अन्य कारी देना नहीं है। अप्रार्थी द्वारा वाहन का उपयोग कर कार्य प्रारंभ कर रहा है जिससे वाहन की प्रदर्शनी नहीं है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी आवश्यक प्रयोजन की आवश्यकता नहीं की गई है। निरस्त करने का प्रयास किया गया है।

यह कि Petroleum products (Maintenance of production, Storage and Supply) Order 1999 G.S.R. 272 (E) dated 16/04/1999. In exercise of the powers conferred by Sec. 3 of the Essential Commodities Act, 1955. (10 of 1955). in order to regulate production, storage and supply of petroleum products in the interest of sustaining public life, economy and protecting consumers interest, the Central Government hereby makes the following Order, namely: इस आदेश के अंतर्गत 2 एम. एल. ऑई में वाहन निर्धारित किया गया है कि "Retail Sale" means sale of petroleum products not exceeding 2500 liters to any one customer at a time. भारतीय सरकार का उक्त आदेश 1999 वर्ष में लागू किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

इस सभा में मा० राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायदुष्टांत आदेश नं० 2018 (1) पैज नं० 534, बजानवानी कर्मवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 - द्वारा एक संशोधित राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण आदेश 1990 और मोटर स्पेट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन तथा कटाव का निवारण) आदेश 2005 और पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और आपूर्ति का संरक्षण) आदेश 1999 (2005 व 1999 के आदेश भारत सरकार द्वारा जारी किये गये) - डीजल और गैस की जम्मी 1000 लीटर से अधिक डीजल प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जमा किया गया - अभिनिर्धारित - 1000 लीटर से अधिक मात्रा में डीजल का अधिग्रहण जो विभिन्न गांवों से परिवहन की प्रक्रिया के दौरान संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किया गया था, वे 2005 और 1999 के नियंत्रण आदेशों के तहत ऐसा करने हेतु अभिवृत्त नहीं थे - अधिग्रहण और जम्मी की कार्यवाही दूधित हुई। पुनरीक्षण स्वीकार की।

इस सभा में मा० राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायदुष्टांत आदेश नं० 2008 (2) पैज नं० 348 बजानवानी सुरेश कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 - द्वारा 482 - आवश्यक वस्तु अधिनियम - द्वारा 3/7 - प्रसंजान लिया जाना पुलिस ने इस आधार पर 1500 लीटर डीजल बरामद किया कि प्रार्थियों के कब्जे में राज्य सरकार की अधिसूचना में अनुज्ञेय सीमा 1000 लीटर से ज्यादा डीजल था - दो व्यक्ति थे जिनके कब्जे में 1511 लीटर डीजल था - प्रार्थी, प्रत्येक व्यक्ति कब्जे का डीजल 1000 लीटर की अनुज्ञेय सीमा में था - प्रार्थी के विरुद्ध प्रसंजान लिखे जाने का आदेश अपास्त किया।

प्रार्थीगण कृपक पेशा व्यक्ति है। डीजल के असत बिल सर्वका बरामदगी अन्वेषणकर्ता को दिये हुए हैं। अप्रार्थीगण द्वारा राज्य सरकार की किसी भी अधिसूचना का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः अप्रार्थी के विरुद्ध स्टेट की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 8ए के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, को स्वरिज कर अप्रार्थी की जम्मा बोलेंगे कैम्प नं० R-31-GA-5205 मय मय 1000 लीटर डीजल मय 05 प्लास्टिक ड्रम एवं कय किये गये डीजल के बिल को वापस लौटाये जाकर जम्मी की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहुस सुनी गयी। राजकीय अभिभावक ने अपनी बहस में कथन किया है अप्रार्थी द्वारा एक डीजल की जम्मी के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तलाशी के दौरान वाहन में पाये गये हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्पों से खरीद किये पूर्व डीजल के बिल की प्रतियों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी हरियाणा से अवैध रूप से डीजल का निरन्तर परिवहन कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाइसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रचना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जम्मा डीजल मय वाहन राजसात किया जाये।

